नेपाल त्रासदी : जब प्रकृति के कोप से कांप उठी हिमालय की घाटियाँ

डॉ. विश्वास तिवारी

'अविश्वसनीय अकल्पनीय और असहनीय? प्रकृति ने एक ही झटके ने हिमालय की शांत वादियों को मातम की चीखों से भर दिया।' मनुष्य अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी समझता है, लेकिन जब प्रकृति अपना क्रोध दिखाती है तो उसका यह घमंड कुछ सेकेण्ड में दूर कर देती है। हिमालय केवल पत्थरों, बर्फ और ऊंची चोटियों की पर्वत-श्रृंखला नहीं है। वह दक्षिण एशिया की मानसूनी व्यवस्था, जैव विविधता और करोड़ों लोगों को रोजगार का भी आधार है। जिस हिमालय को हम स्थिर और अड़िग मानते है वह सबसे युवा, संवेदनशील और सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल की उत्तरी पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भूस्लन ने भारी तबाही मचाई जिसमें बारह सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता है जिसमें लगभग 3 हजार से अधिक विदेशी और भारतीय लोग है। कई लोग मलबे में दब गए है और कई लोग पानी के प्रवाह में बह गए है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक विशाल ग्लेशियर (हिमनद) के ढहने और मलबे के गिरने से हुई। इस आपदा की गति इतनी तेज थी कि लोगों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। चश्मदीदों के अनुसार पानी एक सुनामी की तरह पहाड़ों से नीचे आया और सब कुछ तबाह कर गया। इस आपदा में भारत और नेपाल के साथ उन देशों के नागरिकों ने भी जान गंवाई है जो पर्यटन और तीर्थाटन के लिए नेपाल गए थे और कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए चीन जाने वाले थे। इस प्राकृतिक आपदा के कारण खोजने के प्रयास जारी है, लेकिन मुख्यतौर पर इसके लिए ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे है और हिमालयी क्षेत्र में बार बार तबाही ला रहे है। हर आपदा के बाद जलवायु परिवर्तन रोकने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के उपायों के लिए सहमति बनती है पर उस पर अमल नहीं होता है। इससे निपटने के लिए

हिमालय में बार बार हो रही घटनाओं के लिए यहां के स्थानीय लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां के निवासी तो दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रहे है। नेपाल की इस घटना को कुछ लोग भूंकप से भी जोड़ रहे है, लेकिन आमतौर पर हिमखंड भूकंप से इतने प्रभावित नहीं होते है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा बढ़ते तापमान से होता है जो इन्हें कमजोर करते है और फिर यह खंडित होते है। दुनिया भर में कॉबर्न उत्सर्जन बढ़ने के जो भी कारण है जैसे हमारी जीवनशैली की सुविधाएं, विलासिता लगातार अनियोजित विकास होना और बढ़ती आबादी।

विकसित देश जो सबसे बयादा ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है, उनका सहयोग नहीं मिलता है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते है। अब जब विकसित देश भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे है, जैसे पूरे यूरोप में अब भीषण गर्मी हो रही है अब उनका रवैया जिम्मेदाराना होना चाहिए। नेपाल हमेशा से ही भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ की वजह से सुर्खियां में रहता है खासकर चीन और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में। ग्लेशियर द्वारा निर्मित झीलों की स्थितियों में परिवर्तन की वजह से इस पूरे क्षेत्र में विनाशकारी हादसे होते रहते है। तिब्बती क्षेत्र में कई ग्लेशियर झीलें है और नेपाल की ओर की ढलानदार क्षेत्र में कई रहवासी बस्तियों के कारण इन झीलों के फटने और हिमस्खलन की वजह से बड़े नुकसान की आशंका बनी रहती है।

मानसून के दौरान भारी बारिश, ग्लैशियर में होने वाले बदलाव और हिमस्खलन कम समय में ही बड़ी मात्रा में पानी, पत्थर और मिट्टी निचले तटीय क्षेत्रों में पहुंचा देते है। इस घटना ने 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी, सिक्किम में हुई ल्होनक झील फटने से तीस्ता नदी में 2023 में आई तबाही की याद ताजा कर दी है। हिमालय में पैदा होने वाला यह जल संकट किसी एक देश की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। तिब्बत या चीन के पठार से निकलने वाली यह नदियां नेपाल, भूटान पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तक की विशाल आबादी को प्रभावित करती है।

हिमालय में बार बार हो रही घटनाओं के लिए यहां के स्थानीय लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां के निवासी तो दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रहे है। नेपाल की इस घटना को कुछ लोग भूंकप से भी जोड़ रहे है, लेकिन आमतौर पर हिमखंड भूकंप से इतने प्रभावित नहीं होते है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा बढ़ते तापमान से होता है जो इन्हें कमजोर करते है और फिर यह खंडित होते है। दुनिया भर में कॉबर्न उत्सर्जन बढ़ने के जो भी कारण है जैसे हमारी जीवनशैली की सुविधाएं, विलासिता लगातार अनियोजित विकास होना और बढ़ती आबादी। चीन और अमरिका जैसे देश इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। उससे पिछले 50 वर्षों में अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं खड़ी हुई है। इसे हिमालय ने झेला है। पहाड़ों पर सड़कों के चौड़ीकरण के कारण कटते हुए वृक्ष, सुरंगे, पुल, विद्युत परियोजनाएं और बांध के निर्माण ने इसे छलनी कर दिया है।

इससे छेड़छाड़ के गंभीर दुष्परिणाम सामने आते है नेपाल की इस तबाही में कई बांध भी इसकी चपेट में आए है, सड़के, पुल और इमारत लापता हो गई है। जलवायु परिवर्तन से हम मानसून का स्वाभाविक चक्र खो चुके है। कभी भी कही भी बिना चेतावनी के अचानक भारी बारिश (क्लाउडबर्स्ट) हो जाती है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अनियोजित विकास और सुविधाओं में जुटा हुआ है, जिसका असर पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। अब हमें इस सच्चाई को समझना होगा वर्ना हिमालय के साथ हम कभी न्याय नहीं कर पाएंगें।

मंदिर में मोबाइल बैन से घटे युवा भक्त, आस्था या सेल्फी का संकट

तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित देवराजस्वामी अथि वरदराज मंदिर समेत 52 मंदिरों में एक सितंबर से मोबाइल पर रोक लगा दी गई है। भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के बाद मंदिरों में युवा श्रद्धालुओं की संख्या में 20 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई है। मद्रास हाई कोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश के तहत हम सिर्फ उसे लागू कर रहे हैं, ऐसा मंदिर प्रशासन का कहना है। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या मंदिरों में श्रद्धा बची है या दिखावा हावी हो गया है।

पहले सेल्फी लेते थे, अब मंदिर आना कम कर दिया। पहले युवा सेल्फी लेते दिखते थे, अब ज्यादातर बुजुर्ग श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मोबाइल जमा करने वाले काउंटर पर पहले दिन लंबी लाइन थी, लेकिन अब वहां भी मिडिल एज और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। इससे संकेत मिल रहा है कि कई युवा मंदिर आना कम कर रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ वरदराज मंदिर की नहीं है। राज्य के कई बड़े मंदिरों में भी ऐसा ही असर दिख रहा है।

मंदिर प्रशासन का पक्ष क्या है? देवराजस्वामी मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर. गणेशन ने फुटफॉल घटने की बात मानी, लेकिन फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भक्तों की कमी मुख्य रूप से युवाओं में है। हमें अफसोस है, लेकिन मंदिर की पवित्रता इंस्टाग्राम के लिए कम नहीं की जा सकती। यह बैन मद्रास हाई कोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश के तहत है। हम सिर्फ उसे लागू कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में तिरुचेंदूर सुब्रमणिया स्वामी मंदिर में स्मार्टफोन के दुरुपयोग से जुड़ी पीआईएल के बाद ऐसे बैन का निर्देश दिया था। युवाओं की नाराजगी भी सामने आई है। परंपरा का सम्मान है, लेकिन फोन बिना अनुभव अधूरा। मंदिर की पार्किंग में चेन्नई के 23 साल के अरुण कुमार अपने तीन दोस्तों के साथ पहुंचे थे, लेकिन फोन जमा करने का नियम पता चलते ही उन्होंने कहा कि दादाजी अथि वरदराज के साथ आई थीं, लेकिन काउंटर देखकर बाहर ही रुक गईं। उन्होंने कहा कि दादाजी अथि वरदराज मंदिर में पहले भी आती थीं, लेकिन फोन अंदर नहीं ले जा सकते तो फोटो कैसे लेंगे। वेल्लोर की 19 साल की प्रिया राजेश भी परिवार के साथ आई थीं, लेकिन काउंटर देखकर बाहर ही रुक गईं। उन्होंने कहा कि दादाजी अथि वरदराज दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मैं फोन में लगी पैसे की भी फोटो लेना चाहती थी।

यह पूरा मामला आस्था और तकनीक के टकराव का है। एक तरफ मंदिर प्रशासन और कोर्ट का कहना है कि मंदिर पूजा के लिए है, फोटो स्टूडियो के लिए नहीं। कई बार देखा गया है कि गर्भगृह के सामने लोग सेल्फी लेने लगते हैं, वीडियो कॉल पर दर्शन कराते हैं। इससे पुजारियों को मंत्रोच्चार में बाधा आती है और दूसरे भक्तों की एकाग्रता टूटती है। वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी का तर्क है कि जब तक फोटो नहीं लेंगे तो सोशल मीडिया पर अनुभव साझा कैसे करेंगे और यही अनुभव उन्हें दोबारा मंदिर आने के लिए प्रेरित करता है।

क्या मोबाइल बैन से श्रद्धा बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। अगर युवा केवल फोटो के लिए मंदिर आ रहे थे तो उनका आना कम होना स्वाभाविक है और यह अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि मंदिर में भीड़ कम होने से वास्तविक भक्तों को शांतिपूर्वक दर्शन मिल सकेंगे। लेकिन अगर युवा पीढ़ी मंदिरों से ही दूर हो गई तो भविष्य में हमारी संस्कृति का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है।

20 प्रतिशत की गिरावट छोटी नहीं है। इसका अर्थ है कि हर पांच में से एक युवा ने मंदिर आना बंद कर दिया या टाल दिया। यह आंकड़ा मंदिरों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। प्रसाद, फूल और चढ़ावे की बिक्री पर असर पड़ेगा। लेकिन मंदिर प्रशासन का मानना है कि यह अस्थायी है। धीरे-धीरे लोग आदत डाल लेंगे, जैसे पहले होता था।

पूर्ण प्रतिबंध के बजाय बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जैसे गर्भगृह के अंदर मोबाइल पूरी तरह बैन हो, लेकिन मंदिर परिसर के बाहरी हिस्से में एक निश्चित फोटो प्वाइंट बनाया जाए, जहां लोग फोटो ले सकें। कई बड़े मंदिरों में यह व्यवस्था सफल रही है। इससे पवित्रता भी बनी रहेगी और युवा भी जुड़े रहेंगे।

मोबाइल बैन का उद्देश्य पवित्रता बनाए रखना है, जो सही है। लेकिन पवित्रता के साथ-साथ भागीदारी भी जरूरी है। अगर युवा पीढ़ी ही मंदिर नहीं आएगी तो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? कोर्ट और मंदिर प्रशासन को यह सोचना होगा कि नियम सख्ती के साथ-साथ सहूलियत भी दे, ताकि आस्था और तकनीक दोनों साथ चल सकें और मंदिर केवल बुजुर्गों का ही नहीं, युवाओं का भी केंद्र बना रहे।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

जब रिश्वत विकास से बड़ी हो जाती है तब देश कैसे आगे बढ़ेगा?

देश में संसाधनों की कमी है, इसलिए विकास धीमा है, लेकिन यह आधा सच है। संसाधन तो हैं, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आजादी के बाद हमने बड़े बांध बनाए, बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं, अंतरिक्ष तक पहुंचे, लेकिन एक अदृश्य दीवार हमारे सामने हमेशा खड़ी रही और वह दीवार है भ्रष्टाचार की। यह दीवार ईंट और सीमेंट की नहीं, बल्कि नोट और नीयत की बनी हुई है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को पिछले साल 70 हजार से अधिक शिकायतें मिलीं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात की चेतावनी है कि आम आदमी अब चुप नहीं रहना चाहता। वह बोलना चाहता है। बैंक में कर्ज के लिए, रेलवे में बुकिंग के लिए, नगर निगम में नक्शा पास कराने के लिए, हर जगह उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। सोचिए, जब सबसे ज्यादा शिकायतें उन विभागों से आ रही हैं, जिनसे गरीब और मध्यम वर्ग का रोज का वास्ता है, तो फिर आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर कैसे बचेगा? हम भ्रष्टाचार को केवल घूसखोरी समझकर भूल कर देते हैं। असल में यह उससे कहीं बड़ा है। जब नियमों में बदलाव केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह भी भ्रष्टाचार है। जब भाई-भतीजावाद के कारण योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती, वह भी भ्रष्टाचार है। जब सरकारी फाइल जानबूझकर लटकाई जाती है, ताकि व्यक्ति परेशान होकर पैसे देने पर मजबूर हो जाए, वह भी भ्रष्टाचार है। यह एक तरह से व्यवस्था की हत्या है और हत्या भी रोज।

सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? हकीकत यह है कि डिजिटल की आड़ में भ्रष्टाचार ने नया रूप ले लिया है। पोर्टल पर फॉर्म है, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा बोलकर व्यक्ति को बाहर से मदद लेने को कहा जाता है। बाहर वही दलाल बैठा है, जो पहले टेबल के नीचे पैसे लेता था। अब वह ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लेता है। नाम बदल गया, काम वही है। इसलिए केवल कंप्यूटर लगाने से ईमानदारी नहीं

आएगी। जब तक नीयत नहीं बदलेगी। बैंक, रेलवे और आवास तथा शहरी विकास ये तीन विभाग सबसे अधिक शिकायतों वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां आम आदमी का सपना जुड़ा है। किसान को बैंक से कर्ज चाहिए, ताकि फसल बो सके। छात्र को शिक्षा ऋण चाहिए, ताकि पढ़ सके। मजदूर को रेलवे से टिकट चाहिए, ताकि घर जा सके। गरीब को आवास योजना में मकान चाहिए, ताकि सिर पर छत हो। जब सपनों की फाइल पर ही घूस का बोझ रख दिया जाएगा तो विकास कैसे होगा? ये विभाग अगर ईमानदार हो जाएं तो देश की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी।

भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर अमीर पर नहीं, गरीब पर पड़ता है। अमीर तो पैसे देकर अपना काम करा लेता है, लेकिन गरीब के पास देने को पैसे नहीं होते, इसलिए उसका काम अटक जाता है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, पेंशन लेनी हो, अस्पताल में बिस्तर चाहिए हो, हर जगह उसे धक्के खाने पड़ते हैं। इसी कारण गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर के लिए सिस्टम आसान होता जाता है। यह असमानता ही विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। छोटे भ्रष्टाचार के साथ-साथ बड़े भ्रष्टाचार पर भी नजर डालनी होगी। चुनाव में जिस तरह धन का प्रयोग बढ़ा है, उसने भी इस समस्या को खाद-पानी दिया है। जब चुनाव जीतने के लिए करोड़ों खर्च होंगे तो जीतने के बाद वसूली भी होगी। यह वसूली फिर ठेकों में कमीशन के रूप में दिखाई देती है। ठेकेदार घटिया सड़क बनाता है, क्योंकि उसे कमीशन देना है। अधिकारी आंख मूंद लेता है, क्योंकि उसे हिस्सा मिल गया है और जनता उस टूटी सड़क पर चलने को मजबूर है। यह चक्र तोड़ना जरूरी है। हम हर बार नया कानून मांग लेते हैं, लेकिन कानून पहले से ही हैं। कमी उनके पालन की है। जरूरत इस बात की है कि सजा जल्दी और सख्त मिले। आज भ्रष्टाचार का केस दस-दस साल चलता है। तब तक आरोपी रिटायर हो जाता है या प्रमोशन पा जाता है। इससे डर खत्म हो जाता है। अगर समय-सीमा में जांच और सजा तय हो जाए तो आधा भ्रष्टाचार वैसे ही खत्म हो जाएगा। शिक्षा में हमें स्कूल में ही बच्चों को यह सिखाना होगा कि ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं, ताकत है। जो अधिकारी ईमानदार हैं, उन्हें मंच पर सम्मान मिलना चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ईमानदारी का भी सम्मान है।

हम खुद भी कई बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। लाइन में लगने से बचने के लिए सौ रुपये देना हमें आसान लगता है। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए पचास रुपये देना हमें सुविधा लगती है, लेकिन यही छोटी सुविधा बड़े भ्रष्टाचार की नींव बनती है। अगर हर नागरिक यह ठान ले कि चाहे देर हो जाए, लेकिन घूस नहीं देंगे तो सिस्टम को सुधरना ही पड़ेगा।

विकास का अर्थ केवल फ्लाईओवर और मेट्रो नहीं है। विकास का अर्थ है कि आम आदमी को बिना डर और बिना घूस के उसका हक मिले। जब तक यह नहीं होगा, तब तक बड़ी-बड़ी योजनाएं कागज पर ही चमकती रहेंगी और जमीन पर भ्रष्टाचार की दीवार विकास को रोकती रहेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

समुंदर का बढ़ता स्तर और एक करोड़ चालीस लाख लोगों पर मंडराता खतरा

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया के तटीय शहरों के सामने खड़े खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इसमें मुंबई के साथ कोलकाता और ढाका को दक्षिण एशिया के उन प्रमुख महानगरों में शामिल किया गया है, जहां समुद्र का बढ़ता जलस्तर, तटीय बाढ़ और जमीन धंसने जैसी परिस्थितियां भविष्य में विकराल रूप ले सकती हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर में 50 करोड़ लोगों पर ध्यान देने के साथ मानव विस्थापन, आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे पर जलवायु जोखिम का आकलन करते समय आजीविका और सामाजिक प्रभावों को भी योजनाओं में प्रमुखता देने की जरूरत बताती है।

2024 में वैश्विक समुद्र स्तर 5.9 मिलीमीटर की रिकॉर्ड दर से बढ़ा। यह दर 2014 से 2023 के बीच के औसत से भी अधिक है। यह जलवायु परिवर्तन की गति पहले के अनुमानों से कहीं तेज होने का संकेत है। ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के गर्म होने से पानी का विस्तार हो रहा है और यही विस्तार तटीय शहरों के लिए खतरा बन रहा है।

मुंबई के लिए परेशानी इसलिए है, क्योंकि उसका जोखिम केवल समुद्र स्तर बढ़ने तक सीमित नहीं है। शहर के कुछ हिस्सों में जमीन धंसने (लैंड सब्सिडेंस) और समुद्री खारे पानी की घुसपैठ का खतरा भी मौजूद है। स्टॉर्म सर्ज यानी तूफानी लहरें भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था, आवास और परिवहन ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं। पिछले दस साल में 28 बार चार घंटे में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जो पहले कभी नहीं होती थी। मुंबई तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए खतरा और भी अधिक है।

यूएन ने सरकारों को चेतावनी दी है कि दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे निचले तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह आबादी जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।

कोलकाता, ढाका और मुंबई को एक ही श्रेणी में रखा गया है। ये तीनों शहर घनी आबादी वाले हैं और समुद्र के किनारे बसे हैं। इन शहरों में बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां ड्रेनेज सिस्टम पुराना है और तेजी से हो रहे शहरीकरण ने पानी के प्राकृतिक निकास को रोक दिया है। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बारिश का पानी समुद्र में नहीं जा पाएगा और शहर में ही भरेगा।

अगर समुद्र का स्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2050 तक मुंबई में करीब एक करोड़ चालीस लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वे सबसे निचले इलाकों में रहते हैं और उनके पास बचाव के साधन भी कम हैं। मछुआरा समुदाय, जो समुद्र के किनारे रहता है, उसकी आजीविका भी खतरे में पड़ जाएगी।

मुंबई में एक और खतरा जमीन धंसने का है। कई इलाकों में, जहां पहले दलदल था, वहां भराव करके इमारतें बनाई गई हैं। ऐसी जमीन धीरे-धीरे धंस रही है। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा और जमीन धंसेगी तो दोनों मिलकर खतरे को दोगुना कर देंगे। नवी मुंबई और वसई-विरार जैसे इलाकों में यह समस्या पहले से ही देखी जा रही है।

यूएन की रिपोर्ट सरकारों को सलाह देती है कि वे केवल बड़े बांध और दीवारें बनाने पर ध्यान न दें, बल्कि लोगों के जीवन को भी देखें। सबसे पहले तटीय क्षेत्रों के लिए नई योजना बनानी होगी, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना हो। दूसरी बात यह कि मैंग्रोव को बचाना होगा। मैंग्रोव प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं और तूफानी लहरों को रोकते हैं। मुंबई में पिछले 20 साल में बड़ी संख्या में मैंग्रोव काटे गए हैं। उन्हें फिर से लगाना होगा।

यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आम नागरिक को भी समझना होगा कि प्लास्टिक कचरा नालों में फेंकने से बाढ़ का खतरा बढ़ता है। अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे और पानी के प्राकृतिक रास्तों को नहीं रोकेंगे तो नुकसान कम होगा। साथ ही बिजली और ईंधन का कम उपयोग करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट एक चेतावनी है, न कि भविष्यवाणी। अगर समय रहते कदम उठाए गए तो नुकसान को कम किया जा सकता है। मुंबई ने पहले भी कई आपदाओं का सामना किया है और हर बार उबरकर सामने आई है, लेकिन समुद्र के बढ़ते स्तर का संकट धीमा और स्थायी है। इससे लड़ने के लिए लंबी योजना और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत है। अगर आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को एक डूबता हुआ शहर विरासत में देना पड़ेगा, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

रूस-यूक्रेन युद्ध : ब्लैक सी बना जंग का मोर्चा दुनिया में गेहूं-मक्का महंगा होने का खतरा

तीन सौ से ज्यादा जहाजों पर हमला

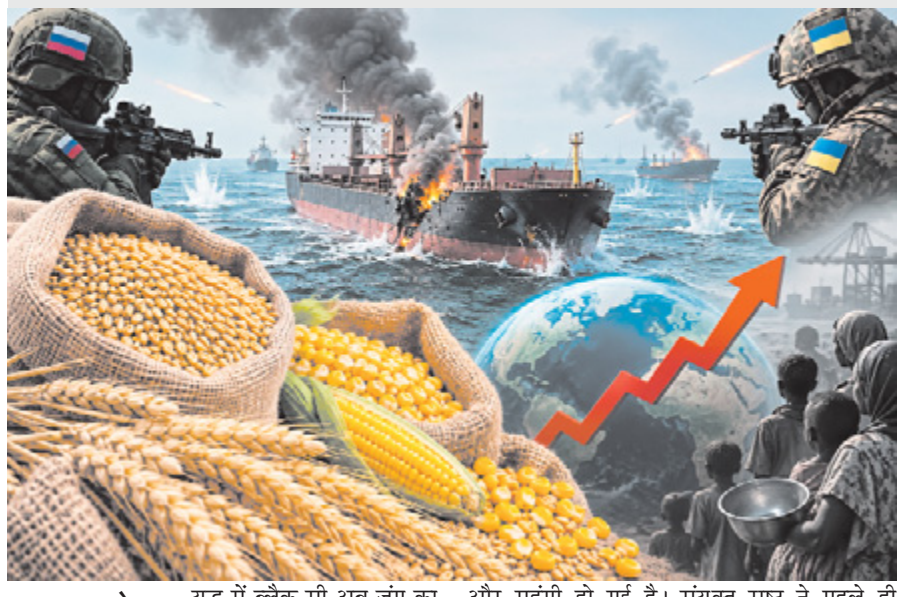

रूस-यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी अब जंग का बड़ा मोर्चा बन गया है। पिछले करीब डेढ़ महीने में दोनों देशों ने तीन सौ से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इनमें अनाज ले जाने वाले जहाज, तेल टैंकर और दूसरे मालवाहक पोत शामिल हैं। लगातार हमलों से ब्लैक सी का समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। जहाज मालिक इस रूट पर जाने से बच रहे हैं और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। इसका असर दुनिया की खाद्य सप्लाई पर पड़ने का खतरा है। गेहूं और मक्का की कीमतों में तेजी आ सकती है। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के करीब 30 प्रतिशत निर्यात का हिस्सा रखते हैं। दोनों देशों का ज्यादातर अनाज ब्लैक सी के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचता है।

पिछले साल के मुकाबले गेहूं 30 प्रतिशत महंगा हुआ है। बंदरगाहों और जहाजों पर हमले बढ़ने से अनाज का समुद्री कारोबार प्रभावित हुआ है। दोनों देशों के गोदामों में अनाज मौजूद है, लेकिन उसे खरीदार देशों तक पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिख रहा है। गेहूं की कीमतें पिछले एक साल में करीब 30 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं।

यूक्रेन ने सड़क-रेल से निर्यात बढ़ाया है। ब्लैक सी का समुद्री रास्ता प्रभावित होने के बाद यूक्रेन सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए अनाज दूसरे देशों तक पहुंचा रहा है। रूस के अनाज निर्यात में 71 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह आंकड़ा बताता है कि युद्ध का असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। अफ्रीका और एशिया के कई देश जो रूस और यूक्रेन से सस्ता गेहूं खरीदते थे, अब उन्हें महंगे दाम पर दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। इससे वहां महंगाई और भुखमरी का संकट गहरा सकता है।

ब्लैक सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से रूस, यूक्रेन के अलावा तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों का व्यापार भी होता है। इस समुद्र के जरिए अनाज के अलावा तेल, गैस और उर्वरक भी भेजे जाते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इस पूरे क्षेत्र में बीमा कंपनियों ने जहाजों का प्रीमियम बढ़ा दिया है, जिसके कारण माल ढुलाई और महंगी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर ब्लैक सी में हमले नहीं रुके तो दुनिया में खाद्य संकट गहरा सकता है। गरीब देशों में, जहां लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, वहां रोटी और महंगी हो जाएगी।

भारत जैसे देश, जो गेहूं का निर्यात करते हैं, उनके लिए यह एक अवसर भी है, लेकिन साथ ही वैश्विक कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में भी दबाव आएगा। जहाज मालिकों का कहना है कि पहले जो जहाज ब्लैक सी में जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे, अब वे जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें युद्ध क्षेत्र का अतिरिक्त बीमा लेना पड़ रहा है और चालक दल को भी ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है। इस कारण प्रति टन लागत कई डॉलर बढ़ गई है। यह लागत अंत में उपभोक्ता की जेब से ही निकलती है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन वह ब्लैक सी पर ज्यादा निर्भर नहीं है। फिर भी वैश्विक कीमतें बढ़ने से भारत के निर्यातकों को फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि घरेलू कीमतें काबू में रहें। पिछले साल भी गेहूं की कीमतों में तेजी के कारण निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। अगर इस साल फिर वैश्विक कीमतें बढ़ीं तो ऐसा कदम फिर उठाना पड़ सकता है। इस समस्या का सैन्य हल नहीं है, बल्कि कूटनीतिक हल जरूरी है। तुर्की ने पहले भी अनाज डील कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अब फिर से ऐसी ही पहल की जरूरत है, ताकि ब्लैक सी में सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जा सके और अनाज के जहाजों को बिना डर के आने-जाने दिया जाए।

रूस-यूक्रेन युद्ध अब केवल सीमा की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया की थाली तक पहुंच गया है। ब्लैक सी में बढ़ते हमले और 71 प्रतिशत निर्यात गिरावट इस बात का संकेत है कि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ सकती है। अगर समय रहते अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दखल नहीं दिया तो गेहूं और मक्का की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब देशों को उठाना पड़ेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)